मनरेगा मजदूरों को अब 162 रुपये मजदूरी

पटना। बिहार में मनरेगा मजदूरों को अब 162 रुपये मजदूरी मिलेगी। बढ़ी हुई मजदूरी पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। दूसरी ओर इंदिरा आवास बनाने के लिए भी सामान्य जिलों में 70 हजार रुपये और उग्रवाद प्रभावित जिलों में 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि केन्द्र सरकार मनरेगा के मजदूरों के लिए 138 रुपये देती है। दूसरी ओर बिहार में न्यूनतम मजदूरी 162 रुपये प्रतिदिन है। नतीजा राज्य में दो तरह की मजदूरी दर लागू हो गई। इससे निचले स्तर पर काफी असंतोष था। विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान 19 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से लगभग 448 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। राज्य में इस वर्ष 1 अप्रैल से ही इंदिरा आवास बनाने के लिए 70 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, जमुई, मुंगेर, सीतामढ़ी और पश्चिम चम्पारण में लाभार्थियों को प्रति मकान 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। केन्द्र इन जिलों को उग्रवाद प्रभावित मानता है। लाभार्थियों का विवरण वेबसाइट पर डालने पर होने वाला खर्च अब केन्द्र सरकार उठाएगी।

पशु आहार पर प्रति किलोग्राम दो रुपये सब्सिडी : राज्य में दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार खरीदने पर प्रति किलोग्राम दो रुपये सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों को अप्रैल-जून 2013 तक संतुलित पशु आहार की खरीद पर खरीद सब्सिडी के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना पर 11.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हिन्दुस्तान 10-07-13